माननीय न्यायाधीश एच एस बेदी और एस सी मलते के
समक्ष

गणेश दास और अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, - उत्तरदाता।

***सी.आर.एम.* 1994 का 4615**
***सी.आर.एम.* 1992 का 3545/M**

10 अगस्त, 1995

दंड प्रक्रिया *संहिता*, 1973 - धारा 156 (3) - कार्यक्षेत्र और मजिस्ट्रेट की शक्तियां - *मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश* देने का *अधिकार नहीं है - धारा 154 के तहत पुलिस के कार्य को धारा 156 (3)* के *तहत मजिस्ट्रेट द्वारा हड़पा नहीं जा सकता* है ।

यह अभिनिर्धारित गया कि तुला राम के मामले में *सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप द्वारा निर्धारित प्रस्तावों को ध्यान में रखते* हुए और बारू राम के *मामले में व्यक्त विचारों के विपरीत दृष्टिकोण लेने वाले निर्णयों की श्रेणी को देखते हुए*, हमारा सुविचारित विचार है कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट को पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। एफ.आई.आर. का पंजीकरण पुलिस द्वारा जांच की शक्तियों के क्षेत्र से संबंधित है, और प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया जाता है। पुलिस के इस कार्य की आवश्यकता नहीं है और न ही हो सकता है। सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा हड़प लिया गया।

(पैरा 12)

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता *आशीष कपूर और वरिष्ठ अधिवक्ता एससी कपूर।*

प्रतिवादी की ओर *से अतुल लखनपाल, वकील .*

निर्णय

न्यायाधीश एस. सी. माल्टा,.

1. इस मामले को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) की व्याख्या के संबंध में परस्पर विरोधी विचारों को ध्यान में रखते हुए कानूनी स्थिति निर्धारित करने के लिए खंडपीठ को भेजा गया है, जो मजिस्ट्रेट को पुलिस को जांच करने का निर्देश देने का अधिकार देता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रश्न उठा :-

सिरसा के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष आईपीसी की धारा 498-ए, 406 और 506 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। उक्त शिकायत प्राप्त होने पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निम्नलिखित आदेश पारित किया -"सुना। शिकायतकर्ता को एफजेआर यू/एस 156 (3) सीआरपीसी के पंजीकरण या जांच और पंजीकरण के लिए संबंधित एस.एच.ओ. को भेजा जाता है।

2. उक्त निर्देश के अनुसरण में, जिला सिरसा के रानिया पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कागजात से संकेत मिलता है कि पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई थी। इस बीच, वर्तमान याचिका इस आधार पर एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर की गई थी कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट पुलिस को मामला दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकता है; और मजिस्ट्रेट की एकमात्र शक्ति शिकायत को जांच के लिए पुलिस को भेजना है। जब यह मामला वीके झांजी, जे की अध्यक्षता वाली एकल पीठ के समक्ष आया, तो दोनों पक्षों के वकीलों ने केस लॉ का हवाला दिया। वकील द्वारा उद्धृत केस लॉ का एक सेट इस तर्क के समर्थन में था कि मजिस्ट्रेट के पास मामला दर्ज करने का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है। दूसरी ओर, प्रतिवादियों के वकील ने इस उच्च न्यायालय के

कुछ मामलों का हवाला दिया, जिसमें यह स्थिति निर्धारित की गई है कि यदि मजिस्ट्रेट प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस को शिकायत भेजता है तो इसमें कुछ भी अवैध नहीं है। रिपोर्ट किए गए निर्णयों में व्यक्त किए गए इन परस्पर विरोधी विचारों के सेट में, मामले को इस खंडपीठ को भेजा गया था, इसलिए, सीमित प्रश्न धारा 156 (3) सी आर.पी.सी. के तहत जांच का आदेश देते समय मजिस्ट्रेट के दायरे और शक्तियों के संबंध में होगा।

3. इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर विभिन्न निर्णयों पर विचार करें, कानूनी प्रावधानों का विवरण लेना सुविधाजनक होगा। सीआरपीसी की धारा 156 में तीन खंड शामिल हैं। पहला खंड मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक संज्ञेय मामले की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्तियों से संबंधित है। दूसरे खंड में प्रावधान है कि ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी की कार्यवाही पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि ऐसे अधिकारी को उस धारा के तहत जांच करने का अधिकार नहीं था। हम मुख्य रूप से तीसरे खंड से संबंधित हैं जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है -

‘156 (1) ... ...

...

धारा 190 के तहत अधिकार प्राप्त कोई भी मजिस्ट्रेट उपरोक्त जांच के अनुसार इस तरह की जांच का आदेश दे सकता है।

यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि धारा 156 दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XII में है जो "पुलिस को सूचना और जांच करने की उनकी शक्तियों" से संबंधित है।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपने संदर्भ क्रम में संदर्भित

निर्णयों के अलावा, बहस के दौरान हमारे समक्ष कुछ और निर्णयों का हवाला दिया गया है। समस्या तब उत्पन्न हुई जब यह देखा गया कि ***बारू राम और अन्य*** **के मामले में निर्धारित कानून*हरियाणा सरकार*** *को* [1]श्रीमती चंपा रानी ***बनाम हरियाणा मामले*** **में रिपोर्ट किए गए मामले में व्यक्त किए गए परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सका/*पंजाब राज्य***।[2] इसलिए, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन दोनों मामलों की जांच अन्य निर्णयों की मदद से भी की जानी चाहिए।

5. बारू राम (सुप्रा) के *मामले में* , दलील यह थी कि मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आदेश पारित करते समय पुलिस को उनके समक्ष दायर शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने का निर्देश देने का अधिकार नहीं था। उस दलील पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की एकल पीठ ने ***देवरापल्ली आदि के एक मामले पर भरोसा किया। बहुत। नारायण रेड्डी***।[3] उस मामले में उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप के समक्ष संक्षिप्त प्रश्न यह था कि क्या कोई मजिस्ट्रेट जो सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से सुनवाई योग्य अपराध का खुलासा करने वाली शिकायत प्राप्त करता है, उसे संहिता की धारा 156 (3) के तहत जांच के लिए पुलिस को भेजने से रोक दिया जाता है। उस पहलू से निपटने के दौरान, उनके लॉर्डशिप ने देखा कि प्रावधान न्याय के लिए अनुकूल है और मजिस्ट्रेट के मूल्यवान समय को बचाता है। इसलिए, शिकायत को जांच के लिए पुलिस को अग्रेषित करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उनके लॉर्डशिप

[1] 1990 (1) आरसीआर 105 = 1990 (1) सीसी मामले 118।

[2] 1990 (3) आरसीआर 577।

[3] 1976 एससीसी (सीआरएल) 380 = एआईआर 1976 एस.सी., 1672.

द्वारा समर्थन किया गया था। इसके बाद उन्होंने सीआरपीसी की धारा 202 के प्रावधानों के साथ इसकी तुलना की और पाया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) और 202 के प्रावधान विभिन्न चरणों में अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष उक्त मामले में, शामिल और उत्तर दिया गया प्रश्न अब हमारे समक्ष मौजूद प्रश्न से सीधे संबंधित नहीं था। *बारू राम (सुप्रा) के मामले में संदर्भित अन्य दो प्राधिकरण 1988* (2) आरसीआर 600 रतन अमोल सिंह बनाम 1988 में रिपोर्ट किए गए मामले हैं। *पंजाब राज्य* और *मेसर्स इंडिया कैरेट प्राइवेट लिमिटेड* बहुत। कर्णाटक *राज्य*[4]उन मामलों से निपटते समय, इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा यह टिप्पणी की गई थी कि इन मामलों का उसके समक्ष शामिल प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने आगे 1986 में रिपोर्ट किए गए एक मामले पर भरोसा किया (1) सीएलआर 67 *हरि सिंह* बनाम हरि *सिंहपंजाब राज्य और एक अन्य* मामले की सूचना जगदीश राय बनाम *जगदीश राय* से मिली है। *पंजाब* सरकार [5] इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आदेश पारित करके पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने और जांच का आदेश दे सकता है। *हरि सिंह* (सुप्रा) के मामले में , इस न्यायालय की एकल पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि मजिस्ट्रेट धारा 156 (3) के तहत आदेश पारित करने और पुलिस को मामला दर्ज करने और जांच करने का निर्देश देने के लिए सक्षम होगा। उस निष्कर्ष के समर्थन में, गोपाल दास *सिंधी बनाम गोपाल दास के* मामले में भरोसा रखा गया था। *असम राज्य*[6] उस मामले में, मजिस्ट्रेट द्वारा

[4] 1989 (1) आर.सी.आर.

[5] 1988 (1) आर.सी.आर.

[6] 1961 SC 986

पारित आदेश था: -

"मामला दर्ज करने, जांच करने और जरूरत पड़ने पर 23 अगस्त, 1957 तक आरोप पत्र दाखिल करने के लिए।

6. उस आदेश को चुनौती देते हुए, प्रस्तुतीकरण का एक मुद्दा यह था कि मजिस्ट्रेट ने उक्त आदेश पारित करते समय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। उस दलील पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप ने कहा कि उक्त आदेश पारित करते समय, मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान नहीं लिया था और धारा 156 (3) के तहत शिकायत को जांच के लिए पुलिस को भेजना उचित था। उस मामले में हालांकि ऊपर उल्लेख किया गया है मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया था, उस फैसले ने सीधे इस सवाल से नहीं निपटा है कि क्या मजिस्ट्रेट का मामला दर्ज करने का निर्देश देना उचित था। ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 156 (3) को पढ़ने पर भी कोई विवाद नहीं है कि मजिस्ट्रेट धारा 156 (3) के तहत आदेश पारित कर सकता है और पुलिस को शिकायत में जांच करने का निर्देश दे सकता है। हालांकि, विवाद इस सवाल पर केंद्रित है कि क्या मजिस्ट्रेट जांच का निर्देश देते समय मामला दर्ज करने का निर्देश भी दे सकता है, और इस तरह पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे सकता है। अत, ऐसा प्रतीत होता है कि एआईआर 1961 एस.सी. 986 में रिपोर्ट किया गया मामला सीधे तौर पर हमारे समक्ष मौजूद मुद्दे से संबंधित नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि ***हरि सिंह*** **(सुप्रा)** के मामले में इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों में एआईआर 1961 एससी 986 में निर्धारित अनुपात पर सही ढंग से विचार नहीं किया गया था। ***बारू राम के*** मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने ऊपर उल्लिखित जगदीश राय ***के मामले का संदर्भ***

दिया । ***जगदीश राय के मामले में,*** इस न्यायालय की एकल पीठ ने कहा था कि शिकायत पर मामला दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट का निर्देश कुछ अनियमित था। हालांकि, लॉर्डशिप ने पाया कि उस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद की जांच अवैध नहीं थी। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि, उस मामले ने भी यह निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत ठोस आधार प्रदान नहीं किया कि मजिस्ट्रेट धारा 156 (3) के तहत आदेश पारित करते समय एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है।

7. याचिकाकर्ताओं के तत्कालीन वकील ने हमारा ध्यान कथित मामले ***विजय कुमार बनाम भारत की ओर दिलाया।करतार सिंह***।[7] उस मामले में उसी एकल न्यायाधीश ने कहा है कि मजिस्ट्रेट के लिए संबंधित पुलिस अधिकारी को मामला दर्ज करने और संहिता की धारा 156 (3) के तहत जांच करने का निर्देश देने के लिए कोई कानूनी रोक नहीं है। उस प्रस्ताव के समर्थन में, उन्होंने हरि सिंह के मामले से भी मदद ली, [8]जिस पर हम पहले ही इस फैसले के पहले भाग में चर्चा कर चुके हैं। *विजय कुमार* (सुप्रा) का मामला उपरोक्त ***बारू राम के मामले*** और उस मामले में संदर्भित अन्य मामलों से भी समर्थन मांगता है। दूसरे शब्दों में ***, विजय कुमार*** के मामले में, यह प्रस्ताव कि मजिस्ट्रेट धारा 156 (3) के तहत आदेश पारित करते समय एफ.आई.आर. के पंजीकरण का निर्देश दे सकता है, फिर से दोहराया गया।

8. इन निर्णयों के संदर्भ में अब हम उस निर्णय पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं जो ऊपर उल्लिखित विचारों के विपरीत

[7] 1991 (1) सी.सी. केस 7,

[8] 1986 (1) सी.एल.आर. (67).

दृष्टिकोण निर्धारित करता है। इस मुद्दे पर सबसे पहला फैसला (*रतन अमोल सिंह* ***बनाम*** **भारत सरकार)** ***में दिया गया है।पंजाब राज्य***[9] और एक अन्य मामला (*केवल राम चौहान* ***बनाम*** **पंजाब में*) रिपोर्ट किया गया।पृथीपाल सिंह बख्शी)।***[10] तदुपरांत, पंजाब राज्य बनाम ***पंजाब राज्य के एक मामले में।जोगिंदर सिंह***[11] ने पाया कि पुलिस अधिकारी ने मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के आधार पर मामला दर्ज किया था। उस बिंदु से निपटते समय, उनके लॉर्डशिप ने पाया कि मजिस्ट्रेट को मामला दर्ज करने का आदेश देने का अधिकार नहीं था। हालांकि, उस बिंदु पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई थी।

9. याचिकाकर्ताओं के वकील ने नरेश कुमार बनाम नरेश कुमार *के मामले को हमारे ध्यान में लाया । हरियाणा राज्य*।[12] उस मामले में इस न्यायालय की एकल पीठ ने पंजाब राज्य बनाम *पंजाब राज्य के एक मामले का उल्लेख किया* था। *कश्मीरा सिंह*।[13] एकल न्यायाधीश ने पंजाब राज्य बनाम पंजाब राज्य के उपर्युक्त मामले को अनुमोदन के साथ उद्धृत *किया। जोगिंदर सिंह ने* आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को रद्द कर दिया और पक्षकारों को उनके दीवानी मुकदमे पर मुकदमा चलाने की स्वतंत्रता दे दी। कश्मीरा सिंह के उपर्युक्त संदर्भित मामले में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि मामला दर्ज करने का निर्देश देने वाला मजिस्ट्रेट का आदेश अनुचित था। उनके लॉर्डशिप ने (*तुला राम* वी) *से समर्थन प्राप्त किया।किशोर*

[9] 1988 (1) आर.सी.आर.
[10] 1988 (2) आर.सी.आर.
[11] 1991 (3) आर.सी.आर.
[12] 1995 (1) आर.सी.आर. 222
[13] 1992 (2) हाल ही में सी.आर.78

सिंह)।[14] बाद के चरण में, हम उस मामले को कुछ हद तक विवरण के रूप में संदर्भित करेंगे। एक अन्य मामले का हवाला दिया गया (*मणि राम* वी। *हरियाणा राज्य)* (13), जिसमें इस न्यायालय की एकल पीठ ने जोगिंदर सिंह (सुप्रा) के मामले पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि मजिस्ट्रेट को संहिता की धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश देते समय मामला दर्ज करने का निर्देश देने का अधिकार नहीं था।

10. यह हमें मामले पर विचार करने के लिए लाता ***है (श्रीमती चंपा रानी* वी। *पंजाब राज्य)***।[15] उस मामले में इस न्यायालय की एकल पीठ ने अन्य मामलों के साथ *बारू राम* (सुप्रा) के मामले पर विचार किया। उस मामले का निपटारा करते समय उनके लॉर्डशिप ने पाया कि ***बरम* राम** का मामला और अन्य मामले मामले में व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं। **बारू राम** धारा-156 जी.पी.सी. के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सही नहीं था। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि *चंपा रानी के मामले में निर्णय* बारू राम के मामले *में दिए गए फैसले के साथ मेल नहीं खाता* है ।

11. इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर उल्लिखित अधिकांश मामलों में, व्यक्त किया गया विचार यह था कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आदेश पारित करते समय, मजिस्ट्रेट को निर्देश देने का अधिकार नहीं था। पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए, हालांकि वह पुलिस को अत्यंत सम्मान के साथ जांच करने का निर्देश दे सकते हैं, हम कहेंगे कि *बारू राम* के मामले में और अन्य मामलों में उस दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त करते हुए, कानूनी स्थिति सही ढंग से निर्धारित नहीं की गई थी।

[14] ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 2401.
[15] 1990 (3) आर.सी.आर.577.

बारू राम के मामले का निपटारा करते समय जिन मामलों पर भरोसा किया गया था, उन्होंने सीधे तौर पर यह निर्धारित नहीं किया था कि वर्तमान में हमारे सामने शामिल प्रश्न के बारे में कानूनी स्थिति क्या है। कानूनी स्थिति को तुला राम बनाम तुला राम के मामले में उनके लॉर्डशिप द्वारा की गई टिप्पणियों की मदद से और स्पष्ट किया जा सकता है। *किशोर सिंह*।[16] उनके लॉर्डशिप द्वारा निर्धारित कानूनी स्थिति को संक्षेप में निम्नानुसार कहा जा सकता है: -

जांच के लिए धारा 156 (3) के तहत आदेश पूर्व-संज्ञान चरण में पारित किया जा सकता है;

जहां एक मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने का विकल्प चुनता है वह निम्नलिखित विकल्पों में से कोई भी अपना सकता है:

सीआरपीसी की धारा 200 के तहत आगे बढ़ें और शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के साक्ष्य दर्ज करें;
प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करें और स्वयं द्वारा जांच का निर्देश दें;
मजिस्ट्रेट प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित कर सकता है और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जांच या पुलिस द्वारा जांच का निर्देश दे सकता है।

शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के बयान पर विचार करने के बाद या जांच और पूछताछ के परिणामस्वरूप मजिस्ट्रेट; यदि ओ'डेड, सामग्री से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायत को खारिज कर सकता है;

12. जहां एक मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 156 (3) के तहत संज्ञान लेने से पहले पुलिस द्वारा जांच का आदेश देता है और उस पर

[16] ए.आई.आर.1977 एस.सी. 2401

रिपोर्ट प्राप्त करता है जो वह कर सकता है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करें और आरोपी को आरोपमुक्त करें, या सीधे आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करें, या उसके सामने दायर शिकायत पर अपना दिमाग लगाएं और संहिता की धारा 190 के तहत कार्रवाई करें।

13. तुला राम (सुप्रा) के मामले में *उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप द्वारा निर्धारित प्रस्तावों* को ध्यान में रखते हुए और बारु राम के *मामले में व्यक्त विचारों के विपरीत दृष्टिकोण लेने वाले निर्णयों की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए,* हमारा सुविचारित विचार है कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट को पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। एफआईआर का पंजीकरण पुलिस द्वारा जांच की शक्तियों के क्षेत्र से संबंधित है, और प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया जाता है। सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस के इस कार्य को हड़पने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) को पढ़ने से संकेत मिलता है कि मजिस्ट्रेट को पुलिस द्वारा जांच का निर्देश देने का अधिकार है, और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की शक्तियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। जांच का आदेश देने का अवसर दो परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकता है, पहला, मजिस्ट्रेट द्वारा मामले का संज्ञान लेने से पहले, और दूसरा, जब वह सीआरपीसी की धारा 202 के तहत आगे बढ़ने का फैसला करता है। पहला है; संज्ञान लेने से पहले चरण, और धारा 156 (3) के प्रावधानों द्वारा कवर किया गया है। मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट ने धारा 202 Cr_P.सी के तहत जांच का निर्देश दिया क्योंकि वह इस मुद्दे को तब तक स्थगित करना उचित समझता है जब तक कि उसे पूछताछ या

जांच के माध्यम से पर्याप्त सामग्री नहीं मिल जाती है, ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सके कि क्या उसे आगे बढ़ना चाहिए और आरोपी को उसके सामने पेश होने के लिए समन जारी करना चाहिए; या क्या उन्हें शिकायत को निराधार बताकर खारिज कर देना चाहिए। ये संहिता की धारा 203 और 204 के तहत शक्तियां होंगी। सीआरपीसी की धारा 156 और 202 के तहत ये दो प्रावधान दो अलग-अलग मंजिलों पर कार्य करते हैं। धारा 156 (3) के तहत निर्देश एक शिकायत में उत्पन्न हो सकता है जो संज्ञेय मामले या गैर-संज्ञेय मामले से संबंधित है। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को जांच करने के लिए कहा क्योंकि इससे उसे अपना समय बचाने में मदद मिलती है। गैर-संज्ञेय मामले में पुलिस द्वारा जांच अन्यथा तब तक संभव नहीं होगी जब तक कि मजिस्ट्रेट ऐसा निर्देश जारी नहीं करता है। संहिता के अध्याय 12 में ये सभी प्रावधान "पुलिस को सूचना और जांच करने की उनकी शक्ति" से संबंधित हैं। कुछ मामलों में जहां अदालत में शिकायत दर्ज की जाती है, मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेने से पहले पुलिस को शिकायत में जांच करने का निर्देश दे सकते हैं। उस स्थिति में पुलिस अधिकारी जांच की उन सभी शक्तियों का पालन करेगा जो वह संहिता के अध्याय XII में दिए गए प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय मामले की जांच करते समय हकदार होगा। तथापि, इन सभी प्रावधानों में मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई निर्देश देने पर विचार नहीं किया गया है। इन टिप्पणियों के साथ, हम संदर्भ को एकल पीठ को लौटाते हैं।

14. *J.S.T.*

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जिज्ञासा शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी